

समाज में नैतिक पतन और मीडिया की भूमिका

पूरे विश्व में भौतिक विकास तो बहुत तेजी से हो रहा है, किन्तु उसके साथ साथ नैतिक पतन भी हो रहा है। विश्व के अनेक देशों में यह नैतिक पतन धीरे-धीरे हो रहा है। किन्तु दक्षिण एशिया के देशों में बहुत तीव्र गति से हो रहा है, और वह गति भारत में और भी तीव्र है। पूरे विश्व में इस नैतिक पतन के कई कारण दिख रहे हैं जिनमें 6-7 प्रमुख हैं—1. संचालक और संचालित के बीच बढ़ती दूरी 2. निष्कर्ष निकालने में विचार मंथन की जगह प्रचार का अधिक प्रभावकारी होना 3. राजनीति और समाज सेवा का व्यवसायीकरण 4. भौतिक पहचान का संकट 5. समाज का टूटकर वर्गों में बदलना 6. निष्प्रभावी राज्य व्यवस्था 7. मानव स्वभाव ताप वृद्धि 8. मानव स्वभाव स्वार्थ वृद्धि। यद्यपि ये सभी समस्याएँ विश्व व्यवस्था पर घातक प्रभाव डाल रही हैं, किन्तु इसमें भी निष्कर्ष निकालने में विचार मंथन की जगह विचार प्रचार अधिक घातक सिद्ध हो रहा है।

भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ निष्कर्ष निकालने के लिये दो इकाईयाँ हैं— 1. सामाजिक निष्कर्ष निकालने के लिये कुछ विचारकों की भूमिका। 2. राजनैतिक निष्कर्ष निकालने के लिए विधायिका अथवा संसद। सामाजिक निष्कर्ष निकालने के मामलों में विचारकों की भूमिका या तो शून्यवत् हो गई है अथवा नगण्य। आज तो स्थिति यह हो गई है कि वास्तविक विचारकों के अभाव में बाबा रामदेव अथवा आशाराम बाबू सरीखे लोग ही विचारक बन बैठे हैं। संसद या विधायिका में भी विचार मंथन की जगह अपने चुनाव क्षेत्र की लोक प्रियता को ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यहाँ तक कि न्यायपालिका में भी सामाजिक लोक प्रियता प्राप्त करने की होड़ मची है। इस लोक प्रियता की होड़ और विचार मंथन का अभाव ही यह परिणाम दे रहा है और अनेक असत्य धारणाएँ समाज में सत्य का स्थान ले रही हैं।

समाज में असत्य धारणाओं को सत्य के समान स्थापित करने के लिये विचार-प्रचार का सहारा लिया जाता है। वास्तविक विचार तो वह होता है जो विचार मंथन के बाद निकला हुआ निष्कर्ष हो, और उस विचार मंथन में भावनाओं की जगह तर्क का सहारा लिया जाये। किन्तु सच्चाई यह है, कि चालाक लोग स्वार्थ वश बिना विचार मंथन के ही किसी बात को लेकर उसका सघन प्रचार शुरू कर देते हैं। इस सघन प्रचार का ही परिणाम होता है कि वह असत्य बात धीरे-धीरे समाज में स्वीकृत हो जाती है, और समाज उसे सच मान लेता है, जबकि उस बात के पीछे ना कोई विचार मंथन होता है न कोई तर्क। सच्चाई यह है कि समाज तो भावना प्रधान होता है, वह तो अनुकरण जानता है। विचार मंथन नहीं है और विचारकों के अभाव में समाज इन नकली विचारकों या राजनेताओं के निष्कर्षों को ही सच मानकर उसका अनुकरण करने लगता है।

इस प्रचार में अन्य अनेक साधनों का तो प्रयोग किया जाता ही है, किन्तु इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिन्ट मीडिया इस प्रचार में बहुत महत्वपूर्ण हो गये हैं। कुछ वर्ष पहले तक ये दोनों, घटनाओं की या विचारों की सूचना देने तक सीमित होते थे। किन्तु वर्तमान समय में मीडिया के ये दोनों साधन खुले व्यवसाय का रूप ले चुके हैं, और अब प्रचार तंत्र के इन दोनों साधनों का सामाजिकता से दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है। मीडिया के ये दोनों माध्यम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज को धोखा देने के लिये स्वयं को प्रचारित करते रहते हैं। किन्तु वास्तविक लोकतंत्र से इनका दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है। यह बात अवश्य है कि भारत के लोकतंत्र के तीन स्तंभ—न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका की अपेक्षा इनका कार्य कम बुरा है। क्योंकि लोकतंत्र के तीन स्तंभ न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका अपने कार्यों को व्यवसाय के रूप में बदलकर अमानत में खयानत जैसा दण्डनीय अपराध करते हैं। जबकि मीडिया अपने को व्यावसायिक रूप में बदलकर भले ही गैर कानूनी अथवा असामाजिक कार्य करता हो किन्तु किसी तरह का सामाजिक अपराध नहीं करता। स्पष्ट है कि हम लोकतंत्र के तीन स्तंभों को अपनी ओर से पावर भी देते हैं और पैसा भी। जबकि मीडिया को हम किसी तरह का ना पावर देते हैं न ही पैसा। इसके बाद भी वे मीडिया कर्मी लोकतंत्र के अन्य तीन स्तंभों की अपेक्षा कम बुरे हैं, तो वे आलोचना के पात्र नहीं हैं।

मीडिया के दोनों स्तंभ पूरी तरह व्यावसायिक हो गये हैं, इसमें अब कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। अरविन्द केजरीवाल ने जो कुछ कहा है वह पूरी तरह सच है। यह अलग बात है कि यह बात कई वर्षों से स्पष्ट दिख रही है। अरविन्द केजरीवाल ने यही बात हिम्मत के साथ कही है जो दूसरे लोग नहीं कहते। कौन नहीं जानता कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ही कुछ लोग एक खबर छिपाने के लिये सौ सौ करोड़ रुपये लेने का प्रयत्न करते हैं। कौन नहीं जानता कि अनेक अखबारों में सच खबर भी छपवाने के लिये कभी कभी पैसे देने पड़ते हैं और पैसे देकर झूठी खबर छपवाना तो बिल्कुल ही आम बात है। मैंने स्वयं अनुभव किया कि अनेक दिनों से जी न्यूज का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिल्कुल स्पष्ट होकर अरविन्द केजरीवाल के खिलाफ अभियान चला रहा था। मैंने स्वयं अनुभव किया कि इंडिया टीवी का नाम, टीम अरविन्द केजरीवाल के एक सदस्य संजय सिंह द्वारा भूल से ले लिये जाने के बाद उसी बात को कई दिनों तक इस तरह रटते रहा कि जैसे कि कोई बहुत बड़ी भूल हो गई हो। मैंने यह भी देखा है कि सम्पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने संगठित और एक जुट होकर एक ओर तो अरविन्द केजरीवाल के इस आरोप का प्रतिवाद किया दूसरी ओर स्वयं ही बार-बार यह बात भी दुहराते रहे कि मीडिया ने ही अरविन्द केजरीवाल को प्रयत्न पूर्वक इतना उपर उठाया है, और उन्हें इसके लिये आरोप लगाने की जगह धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिये। मीडिया के इस कथन का अर्थ यह हुआ कि मीडिया जब चाहे किसी अयोग्य व्यक्ति को आसमान तक उपर उठा सकता है और जब चाहे पाताल तक नीचे गिरा भी सकता है। मैं समझता हूँ कि वर्तमान समय में मीडिया के पास आंशिक रूप से ऐसी अलोकतांत्रिक शक्ति है भी। मैं स्थानीय स्तर पर भी जानता हूँ कि रामानुजगंज के एक लोकप्रिय समाचार पत्र के संवाद दाता से ही कलेक्टर स्तर तक के शासकीय कर्मचारी इतना डरते हैं कि वह गलत काम करके भी एक बड़ा आदमी हो गया है और उसकी गलतियाँ सही मान ली जाती हैं।

मीडिया यदि इस कार्य को व्यवसाय के रूप में करता भी है, तो उसमें गलत क्या है? यदि वह ब्लैकमेल ना करके सीधा-सीधा भी पैसा लेना शुरू कर दे, तो इसमें अपराध क्या है? आखिर सरकारें मीडिया को जितनी बड़ी राशि विज्ञापन के रूप में देती हैं, वह भी तो एक प्रकार का लालच ही है, तो कोई सच खबर छापने या दबाने के लिये किसी मीडिया वाले ने पैसे ले लिया तो, उसमें गलत क्या है? यदि गलत माना जाय तो सिर्फ इतना ही अनैतिक है कि कोई व्यक्ति मुफ्त भोजनालय का बोर्ड लगाकर पैसे से भोजन देना शुरू कर दे, अर्थात् मीडिया के लोग अपने को चरित्रवान, ईमानदार कहते भी रहे और चुपचाप कमाने का व्यवसाय भी करते रहे। इससे अधिक मीडिया का कार्य न कोई अपराध है, न अनैतिक। भ्रष्ट और बेईमान लोग स्वयं को मीडिया से मिलकर असत्य खबरे छपवाते हैं, दूसरी ओर स्वयं को ईमानदार घोषित करने के लिये एक दूसरे पर आरोप भी लगाते रहते हैं। मेरे विचार से अरविन्द केजरीवाल के आरोपों के अनुसार मीडिया उतना दोषी नहीं है जितना भारत के

तीनो लोकतांत्रिक संस्थाएं, जो लगातार स्वयं तो अपराध कर रही हैं तो दूसरी तरफ मीडिया के लिये अनैतिक प्रतिबंध लगा रही हैं। अंत में मेरा यही निवेदन है कि मीडिया को एक व्यवसाय मानकर उनकी अलग अलग विश्वसनीयता को परखने का प्रयत्न करना चाहिये न कि आंख मूंदकर उसमें लिखी बातों को सच मानने का।

पत्रोत्तर

1. विचार— एम एस सिंगला अजमेर राजस्थान, ज्ञान तत्व— 50060 ।

मंहगाई आपके विचार मंथन का प्रमुख विषय रहा है। इसमें आपकी मूल सोच यह रही है कि मंहगाई नहीं है, मुद्रास्फीति है। यह सोच सही है। यहां इन दोनों स्थितियों पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया जा रहा है। देखिये आप उनसे कहां तक सहमत हो पाते हैं। जनता के लिये आम तौर पर मुद्रा स्फीति को समझ पाना मुश्किल होता है।

मंहगाई वस्तु के व्यापार और उत्पाद से संबंधित है। उसकी उपलब्धता को प्रभावित कर दिया तो वह वस्तु उपभोक्ता को न मिल पाने से मंहगी हो जायेगी। यानि जिस वस्तु के लिये 5 रुपये दिये जाते थे, उसके लिये 6-7 रुपये या अधिक दिये जायेंगे। किन्तु माल बाहर आते ही दाम गिर जायेंगे। यह बात अलग है कि दाम गिरने में समय लगता है।

यही बात वस्तु के उत्पादन पर लागू होती है। किसी वस्तु का उत्पादन किसी कारण से गिर गया या उसकी अचानक मांग बढ़ गई तो उस वस्तु की कमी होने पर उसके भाव बढ़ जायेंगे। वस्तु की आपूर्ति होने पर मूल्य फिर सामान्य हो जायेंगे। इस प्रकार मंहगाई वस्तु की मांग और पूर्ति पर निर्भर करती है। यह अर्थशास्त्र का मूल नियम है। मुद्रा स्फीति में ऐसा नहीं होता या नहीं हो सकता। मंहगाई विश्व युद्ध के दौरान बढ़ी थी, क्योंकि युद्ध के लिये आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन को प्राथमिकता देने के कारण जन साधारण की वस्तुओं का अपेक्षित उत्पादन नहीं हो पाता था, किन्तु युद्ध समाप्त होने पर कालांतर में मंहगाई कम हो जाती थी।

मुद्रा स्फीति पत्र मुद्रा की देन है। पत्र मुद्रा न हो तो मुद्रा स्फीति नहीं हो सकती। पत्र मुद्रा जारी करते समय पत्र मुद्रा के एवज में निर्धारित मात्रा में स्वर्ण भंडार रखना अपेक्षित, बल्कि आवश्यक होता है। भारत में ब्रिटिश शासन काल के समय तक इसका पालन हुआ था। साथ ही आंतरिक मूल्यवादी मुद्रा भी चलन में थी। भारत के स्वतंत्र हो जाने पर धीरे धीरे स्वर्ण भंडार कम होने लगा। इसका प्रभाव विशेष रूप में सन 1990 से दिखाई देने लगा। जब चंद्रशेखर के प्रधान मंत्रित्व में 40 टन सोना इंग्लैंड को गिरवी रखा गया था जो वापस नहीं आया। इसके विपरीत संसद में बताया गया था कि सोना छुड़ा लिया गया है। इसी के साथ नरसिंह राव के प्रधान मंत्री काल में उनके आदेश से करोड़ों रुपये की पत्र मुद्रा वैसे ही जारी कर दी गई थी। इस प्रकार मुद्रा स्फीति पत्र मुद्रा की देन है। वास्तविक मूल्य की मुद्रा चलन में होने पर मुद्रा का अवमूल्यन संभव नहीं होता। यही कारण रहा कि नरसिंह राव शासन के दौरान और उसके बाद की सरकारों ने स्वर्ण भंडार की बात छोड़ कर अमरीकी डालर के भंडारण का राग अलापना शुरू कर दिया था और यह बात करके जनता को गुमराह किया गया था। गुमराह इसलिये कि वस्तुतः डालर स्वर्ण का स्थान नहीं ले सकता। दूसरे न तो डालर के एवज में स्वर्ण भंडार रखने की व्यवस्था है और न उसका रूपये के साथ कोई लगाव है। आज भारतीय रिजर्व बैंक की अधिकृत सूचना के अनुसार रिजर्व बैंक में केवल 115 करोड़ रुपये मूल्य का सोना-चांदी और आभूषण हैं, यह एक छलावा है। इससे पूर्व जब मुद्रा स्फीति बहुत हद तक नियंत्रण में थी, रिजर्व बैंक के पास 120 करोड़ रुपये मूल्य के सोने का भंडार सन् 1964 के सोने के भाव से था, जो लगभग 64 रुपये तोला था। इस प्रकार ध्रुव सत्य यही है कि देश में मंहगाई नहीं है। यह सब सरकार की ओर से रचा गया मुद्रा स्फीति का खेल है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह मुद्रा स्फीति इंडिया को इंडोनेशिया की मुद्रा के बराबर ला खड़ा कर दे। भारत का रूपया आज भी इंडोनेशिया के रूपये से लगभग 200 गुना अधिक मूल्यवान है।

भारत के स्वतंत्र होने तक देश में कागज के नोटों के साथ चांदी के रूपये अठन्नी और चवन्नी के सिक्के चलते थे। तब के 1947 के चांदी के एक रूपये का बाजार भाव आज लगभग 900 रूपये है। इस प्रकार तब से मुद्रा स्फीति 900 गुना तो मानी ही जायेगी। परन्तु मुद्रा स्फीति का प्रभाव मौलिक या प्राकृतिक उत्पादन और वैज्ञानिक उत्पादन पर अलग-अलग पडा है। उस समय की कुछ जिन्सों या वस्तुओं के भावों की आज के भावों से तुलना करके मुद्रा स्फीति की बात समझी जा सकती है, क्योंकि भिन्न वस्तुओं की दरों का अनुपात भी एक जैसा नहीं रहा। कुछ उदाहरण प्रस्तुत है।

(दर एक रूपया प्रति ...सेर) गेहूँ 1 सेर, चना 16 सेर ग्वार 15 सेर (अब यह कैश क्राप हो गया है और दो सौ रूपये प्रति किलो बिक रहा है)। घी एक रूपया सेर (तब डालडा का जन्म नहीं हुआ था) दूध चार छः आने सेर सब्जियां औसतन चार आने सेर, ये भाव लगभग है। इन वस्तुओं के आज के भाव से तुलना करके मुद्रा स्फीति का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके बावजूद जैसा कि उपर बताया गया है। सन् 1964 में सोने का भाव 64 रूपये तोला था, तब आज सोना 35,000/ तोले के भाव से मुद्रा स्फीति लगभग 550 हो गई है। देखना यह है कि क्या श्रम मूल्य इसी अनुपात में बढ़ा है या नहीं ? क्या आम जनता के लिये इसे मंहगाई कहा जाना स्वाभाविक है ? एक बात और— तब आज के दामों को देखते हुए यांत्रिक वस्तुएं मंहगी थी, क्योंकि इस क्षेत्र में पर्याप्त विकास नहीं हो पाया था। कुल मिलाकर मंहगाई आम आदमी की जरूरत की वस्तुओं के लिये अधिक पैसा देना ही मंहगाई है।

यहां यह विचार आना स्वाभाविक है कि जो विश्लेषण यहां एक साधारण नागरिक दे रहा है वह तथाकथित देश के बड़े-बड़े अर्थ शास्त्रियों के ध्यान में क्यों नहीं है। इसके समाधान में इतना ही कहना काफी होगा कि उन अर्थ शास्त्रियों के ध्यान से बाते बाहर नहीं है। किन्तु लोकतंत्र में ऐसे अर्थ शास्त्रियों का जनता को लूटने का यही श्रेष्ठ साधन या तरीका बनता है। भारत ही नहीं अन्य लोकतांत्रिक देशों का भी ले देकर यही हाल है। स्वाभाविक है कि लोकतंत्र में जब कोई साधारण व्यक्ति वीआईपी बनेगा या वहां तक पहुंचने के लिये बड़ी धनराशि खर्च करेगा और एडी चोटी का जोर लगाएगा तो क्या वह उसका प्रतिफल उससे नहीं चाहेगा ? इस प्रकार निष्कर्ष यही है कि लोकतंत्र में यह लूट उसका गुण धर्म ही कहा जायेगा।

सरकार को मुद्रा स्फीति से लाभ का एक उदाहरण देख लें— तब आयकर की सीमा 3600/- सालाना थीं। 3600 को 550 से गुणा करने पर 19,80,000/- बनती है किन्तु जो दो लाख भी नहीं है। जो देश मुद्रा स्फीति की चपेट में आ जाते हैं, वे उन देशों के हाथ लुटते हैं

जहां की मुद्रा कठोर होती है। कारण यह है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भुगतान तो पत्र मुद्रा के माध्यम से नहीं होता। वह स्वर्ण के माध्यम से ही होता है। इसका उदाहरण है चीन। अमरीका ने चीन पर उसकी मुद्रा युआन की दर घटाने पर जोर डाला किन्तु चीन नहीं माना। मैं समझता हूँ कि अपनी बात ठीक से प्रस्तुत कर पाया हूँ।

उत्तर— मेरे विचार से मांग और पूर्ति के असंतुलन से अस्थायी रूप से कोई वस्तु महंगी या सस्ती होती है। जिसे वस्तु विशेष का महंगा या सस्ता होना कहा जा सकता है किन्तु यदि सब चीजे महंगी हो जाये तब उसे महंगाई कहेंगे। कुछ वस्तुओं के महंगा होने और कुछ के सस्ता होने को महंगाई नहीं कहा जा सकता। भारत में महंगाई शब्द प्रचलित है जिसका अर्थ है सब वस्तुओं का महंगा होना न कि एक वस्तु का। किसी वस्तु का महंगा या सस्ता होने का आंकलन 3 प्रकार के मूल्यों से किया जा सकता है। 1. प्रचलित रूपये के आधार पर 2. सन 1947 के रूपये के आधार पर 3. क्रय शक्ति के आधार पर। यदि मुद्रा स्फीति बढ़ती है और साथ में क्रय शक्ति भी बढ़ती है तो उसे महंगाई नहीं कह सकते। स्वतंत्रता के पूर्व एक ओर उत्पादन घटा था दूसरी ओर युद्ध के लिये बड़ी मात्रा में नोट छाप लिये गये थे। आम लोगो की क्रय शक्ति उस तरह नहीं बढ़ी जिस तरह वस्तुओं के मूल्य। इसलिये उस काल खंड में महंगाई का बढ़ना कहा जा सकता है। उस काल खंड में मुद्रा स्फीति भी बढ़ी और महंगाई भी। स्वतंत्रता के बाद के लगभग 66 वर्षों में रूपये का भौतिक मूल्य लगभग 82 गुना गिरा है। अर्थात् सरकारी आंकड़ों के अनुसार औसत वस्तुओं के मूल्य सन 1947 के रूपये के आधार पर आज के 82 रूपये के बराबर है। तीन वर्षों में यह 100 रूपये के करीब पहुंच जायेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि उस समय एक रूपये में एक किलो कोई वस्तु प्राप्त होती थी और आज 82 रूपये में प्राप्त होती है, तो वह वस्तु न महंगी हुई है या न सस्ती। यदि हम क्रय शक्ति की तुलना करें तो कुल आबादी की एक तिहाई श्रमजीवियों की क्रय शक्ति 164 गुणों करीब बढ़ी है, अर्थात् दो गुनी हुई है। एक तिहाई बुद्धिजीवियों की क्रय शक्ति लगभग साढ़े छः गुना बढ़ी है, अर्थात् 8 गुना बढ़ी है। एक तिहाई धन प्रधान लोगो की क्रयशक्ति लगभग पांच हजार गुनी बढ़ गई है, अर्थात् चौसठ गुना बढ़ी है। इस क्रय शक्ति का प्रभाव यह पड़ा कि श्रमजीवियों और गरीबों के उपयोग में आने वाली वस्तुओं के आधार पर उनके जीवन स्तर में दुगुने का सुधार हुआ। जिसका अर्थ हुआ कि उनके उपयोग में आने वाली वस्तुएँ 164 गुना भी बढ़ जाती हैं, तो उन पर महंगाई का प्रभाव नहीं पड़ता। हुआ ठीक इसका उल्टा कि उनके उपयोग में आने वाली वस्तुएँ 30-40 गुना ही बढ़ पायी और इसलिये उनके जीवन स्तर में 4-5 गुना तक अंतर दिख रहा है। एक मजदूर को सन् 1947 में एक दिन के श्रम के बदले औसत जितना अनाज मिलता था जो आज बढ़कर एक दिन के श्रम के बदले उससे 5-6 गुना अधिक मिल रहा है। इसका सीधा अर्थ हुआ कि श्रम का मूल्य बढ़ा है, अनाज, कपड़ा आदि का घटा है और जीवन स्तर 4-5 गुना बढ़ा है। उस समय जो लोग हमारे क्षेत्र में कोदो, कुटकी, महुआ, गोलनी, सांवा तक खाते थे, वही लोग बाद में सुधर कर मक्का और जौ खाने लग गये और वही लोग अब गेहूँ, चावल खाने लग गये। फिर भी यदि कोई महंगाई का बढ़ना कहता है तो उसे स्वार्थान्ध ही कहा जा सकता है। क्योंकि वह जानबूझकर स्पष्ट देखते हुए भी महंगाई-महंगाई चिल्ला कर भ्रम फैला रहा है। उस समय के बुद्धिजीवियों का वेतन अथवा अन्य आय के साधन 4-5 सौ गुना तक बढ़ गये हैं। उस समय के बुद्धिजीवी यदि सायकिल का उपयोग करते थे तो आज मोटर सायकिल, टी वी आदि का बेधडक उपयोग कर रहे हैं। बुद्धिजीवी उस समय जितनी कृत्रिम उर्जा का उपयोग करते थे, आज वे अपने दैनिक जीवन में कृत्रिम उर्जा का कई गुना अधिक प्रयोग कर रहे हैं। इसका अर्थ हुआ यदि कोई मिडियम क्लास का व्यक्ति महंगाई से पीड़ित होने की बात करता है, तो वास्तव में वह गाली सुनने से कम अपराध नहीं करता। 33 प्रतिशत आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न वर्ग तो इतना अधिक उपर चला गया कि उसने अपनी बड़ी हुई 64 गुनी क्रय शक्ति के आधार पर कृत्रिम उर्जा का खुला दुरुपयोग किया। उसका ही परिणाम हुआ कि भारत में स्वतंत्रता के बाद कुल आबादी 3-4 गुनी ही बढ़ी है, किन्तु आवागमन सैकड़ों गुना बढ़ गया। इस उच्च वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ने का ही एक परिणाम ये हुआ कि सोना-चांदी और जमीन के मूल्य हजारों गुना उपर चले गये। आज यदि वस्तुओं की महंगाई का आंकलन करें तो सोना चांदी और जमीन मांग बढ़ने और उत्पादन स्थिर रहने के आधार पर बहुत महंगे हुए हैं। दूसरी ओर डीजल-पेट्रोल मांग बढ़ने के बाद भी विदेशों से आयात बढ़ाकर तथा बड़ी मात्रा में विदेशों से कर्ज लेकर मूल्य वृद्धि नहीं होने दी गयी। अन्य सभी वस्तुओं का आंतरिक उत्पादन बढ़ा और इसलिये सारी वस्तुएँ सस्ती हुई हैं। यहां तक कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएँ जैसे घड़ी, फाउंटेन पेन, रेडियो ट्रांजिस्टर, मोबाइल फोन आदि तो मिटटी के भाव हो गये हैं। अब आप ही बताइये कि ऐसी स्थिति में कौन सी ऐसी वस्तु महंगी हो गई है जिसका दुष्प्रभाव किसी भी वर्ग पर पड़ा है। महंगाई का हल्ला तीन प्रकार के लोग अधिक करते हैं—1 राजनीतिज्ञ सत्ता परिवर्तन के लिये 2. बुद्धिजीवी अपना वेतन बढ़वाने के लिये तथा 3. पूंजीपति आर्थिक असमानता पर से ध्यान हटाने के लिये। 33 प्रतिशत श्रम जीवियों के जीवन स्तर तथा क्रय शक्ति में दो गुने का सुधार। 33 प्रतिशत पूंजीपतियों के जीवन स्तर तथा क्रय शक्ति में 64 गुने का सुधार किस प्रकार न्यायोचित कहा जा सकता है ? सरकार चाहे किसी की भी रही हो वह बुद्धिजीवी और पूंजीपतियों से मिलकर महंगाई-महंगाई का प्रचार करती है जो उसके श्रम शोषण के षडयंत्र का ही एक भाग है, आर्थिक असमानता पर से ध्यान हटाकर महंगाई को प्रमाणित करना।

एक प्रश्न और बार-बार उठता है कि भारत के आम लोग महंगाई को महसूस क्यों करते हैं ? एक टीवी चैनल में महंगाई की चर्चा हुई तो न महंगाई के समर्थक अगल-बगल में बैठे दोनो विद्वानों के पास कोई उत्तर था, न श्रोताओं के पास। सब निरुत्तर थे और तब उन्होंने एक प्रश्न श्रोताओं के समझ उछाला कि जितने लोग महंगाई का होना स्वीकार करते हैं वे हाथ उठावें। मैं अकेला था और महंगाई के समर्थन में सारे हाथ उठ गये। मैं निरुत्तर था। आखिर क्या कारण है इसका ? मेरे विचार से किसी व्यक्ति को किसी वेतन पर 1 जनवरी को जितना सामान मिलता है और 2 जनवरी को उसका वेतन 10 प्रतिशत बढ़ जाता है तो उसको 10 प्रतिशत अधिक सामान मिलने लगता है। उसके मन में अधिक सामान मिलने की कल्पना घर कर जाती है। छः महीने के बाद या एक वर्ष बाद जब उसका वेतन बढ़ता है, तब तक उसे मिलने वाली सामान की मात्रा घटकर उस स्थिति तक पहुंच जाती है, जहां उसे दो जनवरी के पूर्व जितना सामान मिलता था। मिलने वाले सामान की प्रतिदिन घटती हुई मात्रा उसे महंगाई का आभास कराती है और अन्य लोग उसकी आभास की पुष्टि कर देते हैं।

मेरे विचार से महंगाई का एक बहुत ही सीधा और सरल समाधान है कि 100 रूपये के नोट को एक नया रूपया बोलना और लिखना शुरू कर दिया जाय तो महंगाई अपने आप घट जायेगी। उसके लिये कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि महंगाई भावनात्मक समस्या है, वास्तविकता से दूर है, और सन 1947 की तुलना में आज के रूपये का सौ गुना मूल्य परिवर्तन महंगाई को समाप्त कर देगा। यहा तक कि डालर भी 60 नया पैसा में मिलने लगेगा। करोड़ पतियों की संख्या अपने आप घट जायेगी। लेनदेन में लिखा पढ़ी भी कुछ कम हो जायेगी।

बड़े- बड़े नोटों का प्रचलन रोकने की रामदेव बाबा की बेसिर पैर की मांग भी अर्थहीन हो जायेगी। सच्चाई यह है कि मंहगाई खत्म हो जायेगी। किसी प्रकार का अलग कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर से एक पैसा और पचास पैसा जिन्दा हो जायेगा और कम से कम एक अस्तित्वहीन समस्या का प्रभाव हीन समाधान हो जायेगा।

आपने घी, गेंहूँ, चावल, दूध आदि के 1947 के मूल्यों का आँकड़ा दिया है वह मेरी जानकारी के अनुसार गलत है। उस समय घी का भाव एक रुपये की अपेक्षा कई गुना अधिक था और गेंहूँ का तीन गुना कम, चना का भाव भी एक रुपये का 16 सेर नहीं था। आप इन आँकड़ों का विवरण भेंजेगे तो स्पष्ट होगा क्योंकि गलत आँकड़ें भ्रम पैदा करते हैं।

2. विचार— हरवंश लाल टांक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। ज्ञान तत्व क्रमांक 12838

राजनीति एवं समाज सुधार की दिशा में आपके पुरुषार्थ एवं प्रयासों की जितनी प्रशंसा की जा सके कम है। इस बाबत अनेक संगठन तंत्र अलग-अलग बैनर तले अद्वितीय प्रयास कर रहे हैं। उनके प्रयासों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। उनकी कार्यशैली में चिन्ता हो सकती है, किन्तु भावनाएँ सुधार की हैं।

गायत्री परिवार द्वारा इस दिशा में जो प्रयास किया जा रहा है वह इन सारे तंत्रों से भिन्न है। इसके उपरी कर्म कांड और बाहरी आवरण मात्र को देख कर कोई व्यक्ति इस तंत्र का अध्ययन करेगा तो वह भ्रमित ही होगा। जिन्होंने भी ऋषि के साहित्य के अंदर झोंका है, उसकी जिज्ञासा बढ़ती चली गयी है। मीडिया एवं प्रचार से सर्वथा परे रह कर विज्ञानवादी आध्यात्म और व्यावहारिक सोच के धरातल पर जो कार्य अब तक हो चुका है, उसे आश्चर्य जनक और अद्वितीय स्तर का आंका गया है।

इस पत्र के साथ उनके द्वारा 1980 के दशक में लिखी गई पुस्तिका भेंज रहा हूँ। कृपया इसे पढ़कर अपनी अभिव्यक्ति अवश्य दीजियेगा। फिर उनका यह चिंतन वर्तमान परिवेश में कितना प्रासंगिक है अथवा आपके विचार से यह वर्तमान परिवेश के अनुरूप कितना परे है।

उत्तर— आपका पत्र मिला। गायत्री परिवार द्वारा प्रकाशित पुस्तिका भी मिली। मैंने उसमें बहुत कुछ पढ़ा भी। मैं गायत्री परिवार से पहले भी जुड़ा रहा। श्री राम शर्मा जी के सम्पर्क में रहा। मैं भी आर्य समाज से जुड़ा रहा हूँ, वे भी जुड़े रहे। मैं मानता हूँ कि गायत्री परिवार कोई संगठन ना होकर एक धार्मिक संस्था है, जो समाज सुधार, चरित्र निर्माण का कार्य पूरी ईमानदारी से करती है। आर्य समाज भी ऐसा ही करता है, किन्तु आर्य समाज तथा गायत्री परिवार में कुछ भिन्नता है। आर्य समाज चरित्र निर्माण के साथ-साथ व्यवस्था परिवर्तन पर भी जोर देता है, जो एक सांगठनिक कार्य है। गायत्री परिवार सिर्फ व्यक्ति निर्माण का कार्य करता है। इस मामले में राष्ट्रीय स्वयं सेवक का ढांचा इन दोनों से अलग है। वह किसी भी रूप में न संस्था का कार्य करती है न व्यवस्था परिवर्तन का। वह पूरी तरह सत्ता संघर्ष का खेल खेलती है। मुझे खुशी है कि गायत्री परिवार इस गंदे खेल से दूर है। फिर भी मैं यह महशूस करता हूँ कि राजनीति जितना समाज में अपना दुष्प्रभाव छोड़ रही है उसे रोकें बिना गायत्री परिवार जैसी संस्थाओं का मिशन पूरा नहीं होगा। यदि कुछ लोगों की आदत बन जाये कि वे निर्लज्ज होकर लगातार सड़क पर गंदगी करते रहेंगे और हम समाज सुधार के नाम पर उस गंदगी को सिर्फ साफ करते रहेंगे तो कभी ना कभी साफ करने वालों की संख्या घटेगी और गंदगी करने वालों की संख्या बढ़ेगी। मैं साफ करने वालों के विरुद्ध नहीं हूँ किन्तु मैं चाहता हूँ कि कोई एक ऐसी संस्था बने जो इन गंदगी करने वालों पर भी रोक लगा सके। मैं सफाई करने वालों को निरुत्साहित नहीं कर रहा किन्तु मैं नहीं चाहता कि सफाई अभियान में लगे गायत्री परिवार सरीखी संस्थाएँ गंदगी करने वालों के अभियान को निरुत्साहित करे। दोनों का उद्देश्य एक है दोनों एक दुसरे के पूरक हैं, दोनों को एक दुसरे के साथ प्रतिस्पर्धा से बचना चाहिये। आपका पत्र भी ठीक दिशा में तथा आदरणीय श्री राम शर्मा जी की पुस्तक इस दिशा को स्पष्ट करती है भले ही उनकी मृत्यु के बाद गायत्री परिवार इस दिशा से कुछ अलग होकर सिर्फ समाज सेवा तक सीमित होता गया। राजनीति से दूर रहने के मैं पक्ष में हूँ किन्तु राजनीतिक गंदगी से दूर रहने के पक्ष में नहीं हूँ बल्कि राजनीति में शामिल हुए बिना उसकी सफाई करने को आवश्यक मानता हूँ। आपने जो पुस्तक भेजी है वह ज्ञान तत्व में प्रकाशित करने योग्य है और मैं उस पुस्तक का प्रकाशन भी इस अंक में करूंगा।

3 समीक्षा— अखलाक अहमद उस्मानी, के जनसत्ता 26 मार्च 2014 में प्रकाशित लेख की

मैंने जनसत्ता 26 मार्च 2014 के अंक में अखलाक अहमद उस्मानी का धार्मिक कट्टरता संबंधी एक लेख पढ़ा। उन्होंने लिखा है कि सउदी अरब तथा कतर दो केन्द्रों पर खड़े होकर ईस्लामिक उग्रवाद की लड़ाई में व्यस्त हैं। दोनों ही चाहते हैं कि दुनिया उनके साथ जुड़े। दोनों ही भारत को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। इसके लिये वे भारत सरकार पर दबाव बनाते रहते हैं। भारत सरकार भी दोनों पर तालमेल बनाकर रखना चाहते हैं। किन्तु समस्या तो यह पैदा होती है, जब भारत के इस्लामिक धार्मिक समूह भी आपस में बंटकर अलग-अलग समूहों में हो जाते हैं, और कुछ लोग सउदी अरब के पक्ष में हो जाते हैं तो कुछ कतर के। यदि वैचारिक समर्थन तक बात सीमित होती तो, कोई विशेष समस्या नहीं थी क्योंकि यह तो उनका आंतरिक मामला था। किन्तु समस्या तो पैदा होती है जब दोनों समूह सक्रियता की दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। इस संबंध में भारत के मुसलमानों को गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिये।

विद्वान लेखक के विस्तृत लेख को मैंने पढ़ा। मेरी सोच कुछ और भिन्न है। यदि कहीं आग हल्की लगी हुई है, तो उसे बुझाने का प्रयास करना चाहिये और यदि प्रचंड अग्नि है, तो उस आग से स्वयं को बचाने का प्रयास करना चाहिये। दोनों प्रकार के निर्णय देश, काल, परिस्थिति पर निर्भर करता है। मुस्लिम देश आपस में लड़-कट कर बर्बाद होंगे, तब धर्म-निरपेक्ष विचार आगे बढ़ पायेगा। उन्हें तो लड़ना ही है और वे मानने वाले नहीं हैं, तो भारत को चाहिये कि दोनों के साथ समान दूरी रखकर अपने को बचाना चाहिये। वर्तमान भारत सरकार इस मामले में कुछ ठीक दिशा में है। फिर भी यदि हम भारत के आंतरिक स्थिति पर विचार करें जिसमें संघ परिवार और इस्लाम के संबंध का प्रभाव भी जुड़ा हुआ है तो मेरे विचार में संघ परिवार भी दुनिया में लड़-भिड़ रहे मुस्लमानों की लड़ाई में एक अलग पक्ष बनकर कूदने को आतुर है। रोकने से संघ परिवार मानेगा नहीं, जिस तरह न सउदी अरब मान रहा है न कतर। तो मेरे विचार में यदि कट्टरवादी मुसलमान आपस में लड़ने मरने को उतावले हैं तो हमें ऐसे लोगों को रोकने के बजाय स्वयं को दूर कर लेना चाहिये। अर्थात् मेरा सुझाव है कि मुसलमानों को ऐसे

टकरावो से स्वयं को दूर कर लेना चाहिये जो या तो संघ परिवार के साथ मुसलमानों का टकराव के लिए उतावले हैं अथवा आपस में। या किसी अन्य मुस्लिम संगठनों से। हिन्दुओं को भी चाहिये कि वह संघ परिवार से दूरी बनाकर रखे। किन्तु हिन्दुओं की अपेक्षा मुसलमानों की जिम्मेदारी कई गुना अधिक बढ़ जाती है। क्योंकि उन्हें तो दोनों मोर्चों पर सफर करना है, और हिन्दुओं को एक मोर्चे पर। दूसरी बात यह भी है कि हिन्दू जन्म से ही धर्म को संगठन से उपर मानता है। इसका अर्थ हुआ कि यदि कोई हिन्दू संघ परिवार से जुड़ता है तो उसका वास्तविक धर्म परिवर्तित हो जाता है जबकि मुसलमान जन्म से ही संगठन प्रधान होता है और उसे संगठन से दूरी बनाने के लिये अपने संस्कार बदलने पड़ते हैं। इस सम्बन्ध में अकलाख भाई ने जो लेख लिखा है वह बहुत संतुलित है और पढ़ने योग्य है।

4. विचार— शिवदत्त बाघा— बांदा उत्तर प्रदेश

आपने ज्ञान तत्व अंक 16 से 28 फरवरी 2014 में लोक सभा चुनावों की समीक्षा प्रकाशित की है। इसे समीक्षा कहें या किसी विषय विशेष पर एक व्यक्ति की निजी राय, जो अपने पाठक को किसी परिणाम तक पहुंचने में मदद करती दिखाई नहीं देती। बकौल समीक्षा, कांग्रेस को दिया गया वोट एक वंश की गुलामी होगी। भाजपा को दिया गया वोट तानाशाही का समर्थन होगा। आम आदमी पार्टी को दिया गया वोट समुद्र में डालने जैसा होगा। अन्य से तानाशाही का खतरा तो नहीं है पर समस्याओं का कोई समाधान भी नहीं है।

पिछले पत्र में मैंने दावा किया था कि इस देश में लोकतंत्र नहीं है। बल्कि एकल जातीय राजतंत्र की जगह बहु जातीय राजतंत्र है। जिसका समर्थन 65—66 वर्षों से कान्सटीट्यूशन आफ इंडिया बराबर कर रही है। एक मात्र चुनावों से लोकतंत्र की पुष्टि नहीं होती चुनाव तो इस व्यवस्था का हिस्सा मात्र है जो सत्ता प्राप्ति की लाइन में लगे समुदाय, संगठनों गिरोहों, की राह आसान बनाते हैं। दूसरा पक्ष लोकतंत्र का वह है जिसे आम आदमी के हित में, जमीन में, शासन—प्रशासन के व्यवहार में अलग दिखना चाहिये।

आतंकवादियों, नक्सलवादियों में कम से कम इतनी तो नैतिकता है कि जो हत्याएं वे कर रहे हैं, उनकी वे जिम्मेदारी लेते हैं। परन्तु इस तथाकथित लोकतांत्रिक व्यवस्था के संचालकों के पास इतना भी नैतिक साहस नहीं है, कि इनकी अव्यवस्था में जो हत्याएं हो रही हैं उसकी जिम्मेदारी ले। कर्ज तले दबे देश के, तीन लाख किसानों ने आत्म हत्या कर ली। बीमारी से दम तोड़ दिये, साधनों की कमी से दम तोड़ दिये, सुरक्षा नहीं तो मारे गये। सरकार बनाने में ये भी मतदाता रहे होंगे पर इनके ही तंत्र में इन्हे क्या मिला?

लोक तंत्र के मुखौटे की आड़ में ही सत्ता के दावेदार वे ठहराये गये जिन्हें विदेशी ताकतों के इशारे पर इस देश के जीवन मूल्यों, आदर्शों, उद्देश्यों व इसके अस्तित्व को मिटाने का कार्य इंच दर इंच करना था। उनके वारिस लोकतंत्र की आड़ में इसे अंजाम तक पहुंचा रहे हैं।

उत्तर— मैंने ज्ञानतत्व अंक 284 में व्यक्तिगत रूप से अपनी राय बताते हुए समीक्षा की है न कि कोई निश्चित निष्कर्ष दिया है या आप सबको कोई सलाह दी है। मैंने सबके गुण दोषों की समीक्षा की है। मैंने वर्तमान लोकसभा चुनाव में न कोई निष्कर्ष निकाला है न कोई समाधान दिया है क्योंकि मेरा निष्कर्ष और समाधान तो यह है कि लोकतंत्र लोक नियुक्त से लोकनियंत्रित तंत्र में बदलना चाहिये। उस दिशा में आप पार्टी आंशिक रूप से बढ़ने की बात करती है बाकी तो कोई बात भी नहीं करता। मैंने “आप” के वोट को समुद्र में डालने की बात जो लिखी है उसके आधे अंश को आपने लिखा है परन्तु आपने उसी लाइन के अंश में लिखा “आप” को दिया गया वोट सार्थक भी हो सकता है, और निरर्थक भी, आत्म ग्लानी से बचाएगा को साथ में नहीं लिखा। आपने आधे अंश को लिखकर अपनी निष्पक्षता को शंका में डाला है।

आपके विचार में भारत में लोकतंत्र नहीं है। मैं नहीं समझता कि आधे भरे हुए ग्लास को खाली गिलास कहना भी उतना ही गलत है जितना भरा गिलास कहेंगे। भारत में लोकतंत्र नहीं है यह कहना उचित नहीं है क्योंकि लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी पहचान होती है, कि उसमें व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। मौलिक अधिकार न इस्लामिक देशों में प्राप्त हैं, न साम्यवादी देशों में, न राजतंत्रों में और न ही तानाशाही के देशों में। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अब तक मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। मैं यह मानता हूँ कि यह भारत का लोकतंत्र अधूरा है। आपने लोकतंत्र को एकल जातीय राजतंत्र की जगह बहुजातीय राजतंत्र की संज्ञा दी है। वह मेरे समझ में नहीं आया कि आपका आशय क्या है। मुझे तो आश्चर्य हुआ कि आपने आत्म—हत्या, साधनों की कमी से दम तोड़ने वाले, या भूख से मरने वाले को सरकार द्वारा की गई हत्या के साथ जोड़ा है। जबकि मेरे विचार में अपनी सोच गलत है। सरकार का दायित्व न आत्महत्या रोकना है, न ही भूख से मरना रोकना, न ही अन्य कार्य। ये कार्य तो राज्य के अतिरिक्त कर्तव्य माने जाते हैं। राज्य के दायित्व तो सुरक्षा और न्याय होता है। जिसकी आपने कोई चर्चा ही नहीं की। नक्सलवादियों द्वारा की गई हत्याएं रोकना राज्य का दायित्व है न कि स्वैच्छिक कर्तव्य। नक्सलवादियों से सुरक्षा राज्य नहीं कर पा रहा है उसके लिये राज्य को जिम्मेदार ठहराने की अपेक्षा आपने नक्सलवादियों की प्रशंसा करके कही न कही भूल की है। कोई व्यक्ति अपराध करे और खुले आम स्वीकार कर ले वह उस व्यक्ति से अच्छा नहीं हो सकता जो अपराधी को दंडित करने का दायित्व पूरा नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि इन विषयों पर आपके विचार और अधिक विस्तार से जानने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि दायित्व पूरा न करके कर्तव्य करना या कर्तव्य के आधार पर उस इकाई का आंकलन करना उचित नहीं। यदि सौ लोगों की जान बचाने के लिये एक निर्दोष व्यक्ति के प्राणों की आवश्यकता है तब भी उसकी सहमति के बिना उसकी प्राण लेना लोकतंत्र नहीं है क्योंकि लोकतंत्र में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी संविधान देता है, और संविधान की रक्षा राज्य करता है।

विशेष विचार

राजनीति में हमारी भूमिका —पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, गायत्री परिवार ।

शक्ति की समीक्षा— राजनीति ने आज मानव जीवन के सभी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया है। इसलिये इसका महत्व बहुत हो गया है। प्राचीनकाल में न्याय और व्यवस्था तक ही शासन का हस्तक्षेप होता था, पर अब उसका क्षेत्र बहुत बढ़ गया है, और जीवन के हर पहलू को राजनीति प्रभावित करती है। शिक्षा, उत्पादन, श्रम व्यवसाय, शासन, न्याय, निर्माण, विज्ञान, शिल्प आदि तो पहले से ही उसके नियंत्रण में पहुंच

चुके हैं। धीरे-धीरे जीवन का हर क्षेत्र राजनैतिक प्रभाव के अंतर्गत आता चला जा रहा है। जहां अधिनायकवाद का प्रधान्य है वहां तो जनता को शासनतंत्र की मशीन का एक पुर्जा मात्र बनकर रहना पड़ता है। जानने सोचने और निष्कर्ष निकालने तक के साधन लोगों के हाथ में नहीं रहते। प्रचार का संपूर्ण उपकरण सरकार के हाथ में रहने से जनमानस को शासन जिधर चाहे उधर मोड़ता बदलता रहता है। ऐसी दशा में यह स्वीकार कर लेना चाहिये कि आज राजनीति की शासनतंत्र की प्रबलता सर्वोपरि बनती चली जा रही है और कल वह समय आयेगा जब व्यक्ति शासन के हाथ का खिलौना मात्र बनकर रह जायेगा।

जन जीवन में अपनी प्रमुखता रखने वाली राजनीति में शासन तंत्र में, यदि कहीं दोष रहते हैं तो उसका दुष्परिणाम सर्वसाधारण को बुरी तरह भोगना पड़ता है। वर्तमान स्थिति में जबकि जन साधारण की नैतिक स्थिति निम्न स्तर की ओर गिर रही है, शासन तंत्र के संचालकों का उच्च चरित्र से, उच्च आदर्शों से पूर्ण होना आवश्यक है। "यथा राजा तथा प्रजा" की उक्ति असत्य नहीं है। बड़ों को देखकर छोटे उनसे प्रभाव ग्रहण करते हैं अनुकरण के लिये अग्रसर होते हैं। प्राचीनकाल में संतो ऋषियों और ब्राम्हणों का राजा और प्रजा सब पर नियंत्रण था। उसका व्यक्तित्व उंचा माना जाता था इसलिये जनता उनकी भावनाओं और प्रेरणाओं से प्रभावित होकर अपनी दिशा निर्धारित करती थी।

अब वह स्थान शासन संचालकों को मिल रहा है। उन्हीं के वक्तव्यों, भाषणों, गतिविधियों और योजनाओं से अखबार रेडियो पुस्तकें भरे रहते हैं। सभा सम्मेलनों में उन्हीं की चर्चा प्रधान रूप से होती है, जन चर्चा का विषय वे ही हैं। किसी बिगाड़ या सुधार के लिये उन्हीं को उत्तरदायी माना जाता है। इतनी उंची स्थिति जिस वर्ग ने प्राप्त कर ली है, उन शासन संचालकों का प्राचीनकाल के संतो और ऋषियों के समान ही आदर्श होना चाहिये, अन्यथा राज्य कर्मचारियों पर ही नहीं, जन साधारण पर भी उसकी प्रतिक्रिया होगी। हीन चरित्र का शासक वर्ग कभी भी जन प्रेरणा का प्रकाश स्तंभ नहीं बन सकता।

देशगत राजनीति पर विचार किया जाये या अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर सभी क्षेत्रों से उच्च चरित्र के मार्गदर्शक की नितांत आवश्यकता अनुभव की जा रही है इसी कमी के कारण समस्त विश्व की जनता क्षुब्ध और निराश होती जा रही है।

संसार के राजनीतिज्ञों के पास सारे साधन मौजूद हैं। उच्च शिक्षा सुविकसित मस्तिष्क, चतुर सलाहकार, विज्ञान, जन सहयोग सभी कुछ तो उन्हें प्राप्त है। कमी केवल उदारता और भावनाओं की है। काश, आज की दुनिया का नेतृत्व किन्हीं महापुरुषों के हाथ रहा होता। काश, गांधी, ईसा, बुद्ध, सुकरात, कन्फ्युशियस सरीखी आत्माओं के हाथों शासनाध्यक्षों का कार्य संचालित हुआ होता तो दुनिया आज की तरह नरक की स्थिति में पड़ी न रहकर स्वर्ग बन गई होती। काश, राजनीति ने कूटनीति धूर्तता का रूप छोड़कर धर्मनीति बनना स्वीकार किया होता तो आज सर्वत्र शान्ति प्रेम और आनंद की ही निर्झरिणी बह रही होती।

सम्पन्नता, शिक्षा, कला, विज्ञान एवं चतुरता बढ़ रही हैं, पर चरित्र बल घट रहा है। संसार में शासन तंत्र अधिक शक्तिशाली बनते चले जा रहे हैं पर उनकी वह विशेषता घट रही है जिसके प्रभाव से जनमानस में प्रेरणा और आशा का संचार होता है। आज जबकि जन जीवन के सारे साधन राजनीति के प्रभाव क्षेत्र में चले जा रहे हैं तो यह आवश्यक है कि उसके नेता एवं संचालकों का व्यक्तित्व चरित्र एवं भावना का स्तर इतना उंचा हो कि दण्ड भय से नहीं श्रद्धा से अवनत होकर लोग उनका अनुसरण करने लग जायें। इसी से जन जीवन में सच्ची प्रगति का संचार हो सकता है। यदि यह क्षेत्र दुर्बल बना रहा "बिल्ली के गले में घंटी न बंध सकी", तो भ्रष्टाचार की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहेंगी। जनता सरकार को दोष देती रहेगी और सरकार जनता का कसूर बताती रहेगी समस्या जहां की तहां उलझी पड़ी रहेगी। अनीति को रोकना और साधनों को बढ़ाना शासन का कार्य है। सबको समान अवसर तथा समान न्याय प्राप्त कराना राजकीय उत्तरदायित्व माना गया है। इन उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिये राज्य कर्मचारियों को न्याय और कानून के प्रति नितांत निष्ठावान निर्लोभी, निष्पक्ष एवं कर्तव्यपरायण होना चाहिये। कानून तो पुस्तकों में बंद रहते हैं। उनका पालन करना और कराना कर्मचारियों का काम है। उनका चरित्रवान एवं उच्च आदर्शवादी होना ही प्रजा की सुख शान्ति की गारंटी हो सकती है। यदि वह शासक वर्ग अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों की उपेक्षा करेगा तो प्रजा का न्याय पर से विश्वास कम होता चला जाएगा और हर क्षेत्र में अनीति पनपेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा तथा निर्भय होकर नाना प्रकार के अपराध करेगा। राज्य कर्मचारियों की कर्तव्यपरायणता को एक ओर रखकर तौला जाय, तो कर्मचारियों की इमानदारी ही अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। इसके अभाव में नाना प्रकार की योजनाएं बनती बिगड़ती रह सकती हैं, पर जनहित समस्या का ठीक समाधान न हो सकेगा।

शक्ति के साथ पवित्रता जरूरी—राजनीति की शक्ति निश्चय ही महत्वपूर्ण है। उसका सुसंचालन जनता के लिये सब प्रकार श्रेयस्कर हो सकता है। संसार के जिन देशों का इन दिनों उत्कर्ष हुआ है, उसमें वहां की सुयोग्य सरकारों का बड़ा श्रेय है। राजनीतिज्ञों में सूझ-बूझ, कुशलता क्षमता-योग्यता का होना आवश्यक है। इसके बिना शासन तंत्र ठीक प्रकार नहीं चल सकता। पर इससे भी अधिक आवश्यकता है शासकों की ईमानदारी। यदि वे आदर्शों के प्रति निष्ठावान होंगे, व्यक्तिगत जीवन में पवित्रता और सेवा का व्रत धारण किये हुए होंगे, तो कम योग्यता होने पर भी उनके कार्यों से जनता का अत्यधिक हित साधन होता चलेगा।

जिन लोगों की दिलचस्पी राजनीति में है उनका कर्तव्य है कि प्रशासन के हर क्षेत्र में ईमानदारी और आदर्शवादिता उत्पन्न करने का प्रयत्न करें। राजनीतिक दलों में से प्रत्येक की नीतियां और घोषणाएँ उत्तम हैं। इनमें से किसी का भी सहारा ईमानदारी के साथ लिया जाये तो उससे देश का उत्थान ही हो सकता है। नीतियां किसी भी पार्टी की बुरी नहीं कही जा सकती। संसार के विभिन्न देशों ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम अपनाकर उन्नति की है। इसलिये आवश्यकता तो इस बात की है कि राजनीति के मर्मस्थल पर हमारा ध्यान हो। नेतृत्व उन लोगों के हाथ में सौंपा जाये जो आदर्शवाद से अपने जीवन का हर पहलू ओत-प्रोत किये हुए रह सकें। सार्वजनिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन इस प्रकार के दो भेद करना उचित नहीं। वस्तुतः चरित्र की सच्ची परीक्षा व्यक्तिगत जीवन में होती है। जो मनुष्य व्यक्तिगत जीवन में दुराचार करता होगा और भ्रष्ट परम्पराएँ अपनाता होगा वह सार्वजनिक जीवन में ईमानदार रह सके, यह कदापि सम्भव नहीं।

शासन की पवित्रता उतनी ही आवश्यक है जितनी धर्म पुरोहित की सदाचारिता। प्रजातंत्र पद्धति के शासन में हर मतदाता का परम पवित्र कर्तव्य है कि वोट देते समय किसी लोभ या पक्षपात से प्रेरित होकर मतदान न करे वरन् आदर्शवादी व्यक्तित्वों को ही सर्वोपरि स्थान दें, और यह भी देख-रेख रखे कि शासन तंत्र में चरित्र भ्रष्टता तो बढ़ने नहीं लगी। यदि किसी राष्ट्र को अपना स्वस्थ विकास करना हो तो शासन तंत्र की सच्चरित्रता का पूरा ध्यान रखे। प्रजा की ओर से अधिकारियों को प्रलोभन देकर कोई अनुचित कार्य कराने का प्रयत्न न किया जाय,

और कर्मचारी जनता को परेशान करने की शक्ति का दुरुपयोग करके जनता के शोषण की विवशता उत्पन्न न करने पायें। ऐसी व्यवस्था बनाना उन लोगों का कार्य है जिनके कन्धे पर शासन तन्त्र चलाने का उत्तरदायित्व पडा हुआ है।

राजनैतिक दृष्टि से हम सफल हुए या असफल ? इसका एक ही प्रमाण हो सकता है कि शासनतन्त्र के संचालकों और नागरिकों में कर्तव्यपरायणता एवं नैतिकता कितनी बढ़ी ? इस कसौटी पर जो शासन खरा उतर सकेगा, उसे ही इस राजनैतिक सफलता का श्रेय मिलेगा। इतिहास साक्षी है कि जब भी, जहाँ भी, नैतिक दिवालियापन बढ़ा है, तब उसका परिणाम सर्वनाश के रूप में प्रस्तुत हुआ है। इसलिए यदि राजनीति की प्रचण्ड शक्ति से राष्ट्र को लाभान्वित करना अभीष्ट हो, तो एक ही काम पर सर्वोपरि ध्यान रखें और वह है शासकीय कर्मचारियों की सज्जन्ता एवं उसके फलस्वरूप जनता में उत्पन्न होने वाली उत्साहवर्द्धक प्रतिक्रिया। राष्ट्र इसी नीति पर चलते हुए उठते और बढ़ते हैं।

धर्मतन्त्र का सहगमन जरूरी— लोग एक प्रश्न अक्सर करते रहते हैं कि “हम राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश क्यों नहीं करते ? और राजतन्त्र को अपने अनुकूल सरकारी स्तर पर वह सब सहज ही क्यों नहीं करा लेते ? जिसके लिए इन दिनों इतनी अधिक माथापच्ची कर रहे हैं।” इस सुझाव के पीछे अपनी-अपने संगठन की वह क्षमता और व्यापकता है, जिसका वही मूल्यांकन कर सकने वाले लोग अनुभव करते हैं कि इन दिनों अपना तन्त्र किसी भी राजनैतिक, सामाजिक या धार्मिक तन्त्र से कम प्रखर एवं कम सशक्त नहीं है।

वर्तमान युग में राजनीति की सर्वोपरि सत्ता और महत्ता को स्वीकार करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। यह स्वीकार करने में हमें कोई अडचन नहीं है कि सरकारें यदि सही कदम उठा सकें, सूझ-बूझ से काम लें, और अपने क्रियातन्त्र को सुव्यवस्थित रख सकने में समर्थ हों, तो वे अपने क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति कर सकती हैं। जापान, चीन, रूस, जर्मनी, अरब, इजराइल आदि ने चन्द दिनों के भीतर अपने ढंग से अपनी योजना अनुसार अभीष्ट परिवर्तन के प्रकार प्रस्तुत कर लिए। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो वास्तविकता की ओर से जान-बूझकर आँखें बन्द किये रहें। धर्म का राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं, यह दूसरों ने भले कहा हो हमने यह शब्द कभी नहीं कहे हैं। इतिहास ने हमें सिखाया है कि धर्म की स्थापना में राजनीति का सहयोग आवश्यक है और राजनीति के मदोन्मत्त हाथी पर धर्म का अंकुश रहना चाहिए। दोनों एक-दूसरे के विरोधी नहीं, पूरक हैं।

इतिहास साक्षी है कि गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन और रघुवंशियों के शासन क्रम में उस सतयुग की स्थापना की थी, जिसे हम राम राज्य के नाम से आदर के साथ याद करते हैं। चाणक्य के मार्गदर्शन से गुप्त साम्राज्य पनपा, फैला और परिपुष्ट हुआ था। पाण्डवों का मार्गदर्शन कृष्ण ने किया था और दुशासन का उन्मूलन कर सुशासन की स्थापना की थी। राजा मान्धाता का सहयोग शंकराचार्य की दिग्विजय का महत्वपूर्ण आधार था। भगवान बुद्ध के प्रभाव से सम्राट अशोक का बदलना और अशोक सत्ता के सहयोग से बुद्ध धर्म का समस्त एशिया में फैल जाना एक ऐसी सच्चाई है, जिससे इन्कार नहीं किया जा सकता। समर्थ गुरु रामदास जानते थे कि धर्म प्रवचनों से ही काम चलने वाला नहीं है, सुशासन की स्थापना भी आवश्यक है। अस्तु उन्होंने शिवाजी जैसे अपने प्रधान शिष्य को इस मार्ग पर अग्रसर किया। गुरुनानक का पंथ एक प्रकार से स्वाधीनता में ही बदल गया। उन्होंने “एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला” का आदर्श प्रस्तुत करके यह बता दिया कि राजतन्त्र और धर्मतन्त्र को विरुद्ध दिशाओं में नहीं चलने देना चाहिए।

भगवान का धर्म से ही सीधा सम्बन्ध जुड़ता है पर अधर्म के अभिवर्द्धन के प्रधान कारण दुःशासन को बदलने के लिए वे समय-समय पर अवतार करते हैं। द्रोणाचार्य कहते हैं कि —हम वेदों को आगे रखकर लोगों को समझाने और सन्मार्ग पर लाने का प्रयत्न करते हैं। साथ ही पीठ पर धनुष-बाण भी रखते हैं। दोनों शक्तियों के समन्वय से ही समस्याएँ सुलझती हैं।

उपर्युक्त सत्य का प्रतिपादन करने वाले तथ्यों से इतिहास के पन्ने भरें पड़े हैं। महात्मा गाँधी जिन्हें इस युग का धर्म पुरुष कह सकते हैं, अपनी जीवन साधना से राजनीति का प्रधान समन्वय करके यह आदर्श प्रस्तुत करते रहे हैं कि धर्म और राजनीति एक-दूसरे के विरोधी नहीं पूरक हैं। लोकमान्य तिलक, महामना मालवीय, स्वामी श्रद्धानंद जैसे धर्मवेत्ता मनीषियों ने अपनी धर्म साधना के साथ राजनीति को भी अविच्छिन्न रूप से जोड़े रखा।

शासन आज जिस तरह जीवन के हर पक्ष में प्रवेश करता चला जाता है और धीरे-धीरे व्यक्ति जिस तरह राज्य की कठपुतली बनने जा रहा है, उस बारीकी को समझने वाला कोई सूक्ष्मदर्शी व्यक्ति राजनीति से सर्वथा धर्म की कल्पना भी नहीं कर सकता। जो धर्म को राजनीति से अलग होने की बात कहते हैं उन्हें नितान्त भोला ही कहा जा सकता है। प्रतिकूल राजनीति में धर्म को जीवित रहना भी सम्भव नहीं। रूस, चीन, आदि साम्यवादी देशों में धार्मिकता की कैसी दुर्गति हुई है यह सबके सामने है। तिब्बत का धर्म शासन करने वाले लामाओं को राजनैतिक प्रतिकूलता ने कहीं से लाकर कहीं पटक दिया। राज्याश्रय पाकर ईसाई चर्च कितनी प्रगति कर रहा है और मध्य युग में राज्याश्रय ने इस्लाम धर्म के विकसित होने में कितनी सहायता की ? इन तथ्यों से कोई मूर्ख ही आँखें मीच सकता है।

हमारी दिशा धारा— इस सन्दर्भ में हमारा मस्तिष्क बहुत साफ है। शीशे की तरह उसमें पूर्ण स्वच्छता है। बहुत चिन्तन और मनन के बाद हम एक निष्कर्ष पर पहुँचे हैं और बिना लाग-लपेट, छिपाव एवं दुराव के अपनी स्वतन्त्र नीति निर्धारण करने में समर्थ हुए हैं। हम सीधे राजनीति में प्रवेश नहीं करेंगे। हम राजनीति को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और यही अन्त तक करते रहेंगे। अपना संगठन यदि अपने प्रभाव और प्रकाश को सर्वथा तिरस्कृत नहीं कर देता, तो उसे भी इसी मार्ग पर चलते रहना होगा।

भारत की वर्तमान राजनैतिक रीति-नीतियों, शासन की गतिविधियों और तन्त्र की कार्यप्रणाली पर आमतौर से सभी को असन्तोष है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद कई वर्षों की लम्बी अवधि में जो हो सकता था वह नहीं हुआ। तथाकथित आर्थिक प्रगति की बात भी विदेशी ऋण और युद्ध स्थिति तक बढ़ती हुई बेकारी गरीबी को देखते हुए खोखली है। नैतिक स्तर उपर से नीचे तक बहुत गिरा है। गरीब अधिक गरीब बनें हैं और अमीर अधिक अमीर। शिक्षा की दिशा में घोर निराशा ही हुई है। अपनी इस राजनैतिक और प्रशासकीय असफलता पर हम में से हर कोई चिन्तित और दुःखी है। जिन्हें अधिक क्षोभ है, वे उदाहरण प्रस्तुत करते शासन-कर्ताओं की कटु शब्दों में भर्त्सना करते सुनते हैं और अमुक पार्टी को हटाकर अमुक पार्टी के हाथ में शासन सौंपने की बात का प्रतिपादन करते हैं।

हमारे चिन्तन की दिशा अलग है, हम अधिक बारीकी से सोचते हैं। शासन की असफलता से हम दुःखी हैं। हमें बहुत खेद है कि विगत कई वर्षों में जितना बढ़ा जा सकता था, उतना नहीं बढ़ा गया। प्रगति कुछ भी न हुई हो सो बात नहीं, पर गाँधी जी के धर्म राज्य की, रामराज्य और विश्व मंगल की आध्यात्मिक प्रगति तो अभी लाखों मील आगे की बात है।

गॉंधी जी की दृष्टि— इन विभिन्न परिस्थितियों से देश को उबारने के लिए यों छुट-पुट प्रयत्न बहुत पहले से चल रहे थे पर उन्हें सुसंगठित और सुसंचालित होने का श्रेय गॉंधी जी के नेतृत्व को मिला। वे असली कारण जानते थे और प्रयत्नशील थे कि रचनात्मक कार्यों और बौद्धिक जागरण, स्वतंत्र चिन्तन के माध्यम से प्रजा के मनोबल, चरित्र स्तर, स्वाभिमान एवं शौर्य को जगाया बढ़ाया जाए। स्वतंत्रता संग्राम वे धीरे-धीरे चला रहे थे। क्रांतिकारियों से उनके मतभेद का मूल कारण यह था कि वे चाहते थे स्वराज्य धीरे-धीरे उस क्रम से आये जिस क्रम से देश उसे सँभालने योग्य प्रतिभा अपने में पैदा कर ले।

स्वतंत्रता संग्राम के साथ चरखा, खादी, हरिजन सेवा, ग्रामोदयोग, राष्ट्रीय शिक्षा, सफाई जैसी प्रवृत्तियों को जोड़ देना यों बहुत अटपटा लगता है। असहयोग आन्दोलन और सत्याग्रह की दार्शनिकता कितनी ही उँची क्यों ना हो ? पर उसका व्यवहारिक पक्ष यह था कि इन सरलतम उपायों द्वारा जनता अपनी मूल चेतना विकसित करे और स्वराज्य धारण कर सकने में समर्थ हो जाये। वे जानते थे कि विभूति प्राप्त करने से अधिक कठिन उसे पचाना होता है। शक्ति की असली परीक्षा कोई सफलता प्राप्त कर लेना भर नहीं है; वरन् उसके सदुपयोग से ही प्राप्तकर्ता का गौरव आँका जाता है। भागीरथ गंगा अवतरण की पृष्ठभूमि बनाने में सफल हो गये थे, पर उस धारा को सुव्यवस्थित रूप में प्रवाहित करने के लिए शंकर जी को अपनी जटाएँ फैलानी पड़ीं। यही सर्वत्र होता है। क्रांतिकारी कहते थे कि शस्त्र धारण किये बिना अंग्रेज जाने वाले नहीं हैं। बात उन्ही की सच निकली। सन् 1942 में क्रांतिकारी तोड़-फोड़ ने सिद्ध कर दिया कि असहयोग सत्याग्रह नहीं शस्त्र धारण ही वर्तमान स्थिति में राज क्रांतियों की अनिवार्य आवश्यकता है। इस तथ्य को गॉंधी जी भी जानते थे। अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने जब भारत को स्वराज्य दिला ही दिया था, तो वे इन असामयिक उपलब्धियों से जितने प्रशन्न थे, उतने ही चिन्तित भी। जन-जागरण का प्रायोजन पूरा नहीं हो सका था। इसलिए उन्हें चिन्ता थी कि इस गंगावतरण का सुसंचालन कैसे होगा ?

उन दिनों उन्होंने एक अति महत्वपूर्ण सुझाव रखा था कि काँग्रेस लोकसेवी संस्था का रूप धारण करे और जन जागरण के नितान्त आवश्यक कार्यों में ही जुटी रहे। राजतंत्र चलाने के लिए एक उस स्तर के लोगो की पिछली पंक्ति बना दी जाए। प्रजा पर प्रभाव रखकर काँग्रेस, राजनेताओं की नियुक्ति एवं उनकी रीति-नीति पर नियंत्रण करे, पर स्वयं उससे पृथक रहकर वह जन-मानस के परिष्कार का मूल प्रायोजन पूरा करे, जो किसी राष्ट्र की सर्वतोमुखी प्रगति का यहाँ तक कि सुशासन का भी मूल आधार है।

चूक हुई, दिशा बिगडी— उन दिनों परिस्थितियाँ विचित्र थीं। काँग्रेस नेता गॉंधी जी से सहमत न हो सके। सारी शक्ति राजतंत्र को सँभालने में लग गई। रचनात्मक कार्यों में विश्वास करने वाले लोकसेवी भी उसी तंत्र में खप गए। सबका ध्यान सत्ता की ओर चला गया। सत्ता एक नशा है, उसका चस्का जिसे लगा कि फिर वह उसी घाट का हो लिया। काँग्रेस और उसका परिवार उसी दिशा में चल पडा। जन जागरण के लिए जिन रचनात्मक एवं संघर्षात्मक कार्यक्रमों की जरूरत थी। वे या तो विस्मृत हो गये या उनकी लकीर पिटती रही। अन्य छोटी-बड़ी राजनैतिक एवं सामाजिक स्तर की संस्थाओं का भी यही हुआ। उन्होंने भी अपनी बड़ी बहन का अनुकरण किया। अपना बाहरी जामा वे कुछ भी बनाये रही हों, भीतर ही भीतर सत्ता संघर्ष के लिए चल रही विभिन्न पार्टियों की प्रतिद्वन्द्विता में ही वे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में शामिल थीं। ध्यान बँटा सो बँटा। पिछले कई वर्षों में जिस बौद्धिक, नैतिक एवं सामाजिक क्रांति की जरूरत थी, शिक्षा और कला के महान माध्यमों को सृजनात्मक दिशा में लगाने के लिए उन्हें हथियाना या अपनाया जाना चाहिए था, उस दिशा में किसी ने कुछ नहीं किया। इस भूल को हम ईमानदारी से स्वीकार कर लें, तो कोई हर्जा नहीं है।

दिशा भूलने का जनमानस में हजार वर्ष की गुलामी की कुस्कारी प्रक्रिया को हटाने की उपेक्षा करने का जो परिणाम होना चाहिए था, वह सामने है। उन परिस्थितियों, उत्कृष्ट राजनेतृत्व एवं आदर्श शासन तंत्र की आशा रखना व्यर्थ है। राजनेताओं का चुनाव होता है। चुनावों द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं और उनके चुनाव से सरकारें बनती हैं। जनता का जो स्तर है उसमें चुनाव जीतने के लिए पैसे को पानी की तरह बहाने की जाँति-पाँति के नाम पर लोगों को बरगलाने की, व्यक्तिगत या स्थानीय लाभ दिलाने के सब्जबाग दिखाने की अनिवार्य आवश्यकता पडती है। जो यह सब तिकडमें भिड़ाने में समर्थ न हों, उसका चुनाव जीतना कठिन है। जनता का स्तर ही ऐसा है कि वह वोट का मुल्य और उसके दूरगामी परिणामों को अभी समझ ही नहीं पायी। इसलिए चुनाव में वे लोग जीत न सके, जो रामराज्य स्थापित कर सकने में सचमुच समर्थ हो सकते थे। जनता ने अपने स्तर के विधायक चुने। उन विधायकों ने अपने स्तर की सरकारें बनायीं, उन सरकारों के संचालकों ने वही किया जो जनता कर रही है या कर सकती है। जड के आधार पर पत्तें बनते हैं। धतूरे के बीज से उगे पौधे पर शहतूत कहाँ से लगे ?

राज्य शासन के संचालन में जो व्यक्ति काम करते हैं, उनकी मनोभूमि एवं कार्यशैली ही शासन तंत्र के संचालन का स्वरूप निखारती है। सरकार कई योजनाएँ बनाती और चलाती है, पर उसका स्वरूप जनता तक पहुँचते-पहुँचते विकृत हो जाता है, क्योंकि जिनके हाथ में उस प्रक्रिया के संचालन का भार है, वे उतने शुद्ध नहीं होंगे, जितने होने चाहिए।

अपराधों के रोकने की जिम्मेदारी जिस मशीन पर है यदि उँचे स्तर की हो और भावनापूर्वक काम करे, तो निस्सन्देह अपराधों का उन्मूलन हो सकता है उपयोगी कार्यों के लिए ऋण या अनुदान बँटने वाली मशीन यदि स्वच्छ हो, तो वह धन सचमुच सम्पत्ति और सुविधा बढ़ाने में समर्थ हो सकता है। शिक्षा देने वाली मशीन यदि भावनाओं से ओतप्रोत हो तो छात्रों को ढालने में उन व्यक्तियों का जादू आश्चर्यजनक ढलाई का प्रतिफल प्रस्तुत कर सकता है। सरकारी कानूनों या योजनाओं में दोष नहीं है जितना कि प्रस्तुत प्रक्रिया का संचालन करने वाली मशीनरी की आदर्शवादी भावनाओं का न्यूनतम रूप है।

अब करना है भूल सुधार— प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह शासन संचालन करने वाली मशीन कैसे उत्कृष्ट बने ? सरकारी कर्मचारी आकाश से नहीं उतरते। वे जनता के ही बालक होते हैं। उनसे अपने घर-परिवार से सम्बद्ध समाज में जो कुछ देखा, सुना, समझा, अनुभव किया है, उसी के आधार पर उनका मानसिक स्तर एवं चरित्र ढला है। नौकरी पाते ही वे उन संस्कारों को भुलाकर देवता बन जायें, यह आशा करना व्यर्थ है। एक सच्चाई है कि प्रजातंत्र में जनता के स्तर की ही सरकार बनती है और उसी स्तर की सरकारी मशीन चलती है। पार्टियों की सत्ता बदले, इससे कुछ बनता बिगडता नहीं। पिछले कुछ दशकों में किसी पार्टी विपक्ष का एकाधिकार नहीं रहा। कई पार्टियों की अलग या सम्मिलित सरकारें बनीं। उन्होंने भी कोई अलग आदर्श प्रस्तुत नहीं किया। जिस कीचड में बड़ी पार्टियों का छकडा घिसट रहा था, उसी में खडखडियाँ भी धँस गईं। मूल समस्या यही है। किस पार्टी की सरकार बने, वह किन योजनाओं को कार्यान्वित करे, चुनाव बिना खर्च कैसे कराएँ, उपयुक्त व्यक्तियों को चुनने का जनस्तर कैसे बने ? और सरकारी मशीन में पुर्जे बनने वाले कर्मचारी घर से ही आदर्शवादी और

भावना सम्पन्न बनकर वहाँ तक कैसे पहुँचे ? प्रजातन्त्र की जड़ जनता है। जहाँ जनता का स्तर उँचा होगा वहीं प्रजातन्त्र सफल हो सकेगा। हमें यदि प्रजातन्त्र पसन्द है, तो उसकी सफलता की अनिवार्य शर्त जनता का भावनात्मक एवं चारित्रिक स्तर भी उँचा उठाना ही पड़ेगा।

हम जानते हैं कि जनमानस के अंतरंग का स्पर्श करने और कोमल भवनाओं को संवेदनशील बनाने की क्षमता राजतन्त्र में नहीं है। उसकी मूल प्रकृति और प्रवृत्ति दूसरी है। कूटनीति, राजनीति का पर्यावाची बन गई है। उस स्तर में जो कुछ होगा लोग उसमें अकारण ही किसी कूटनीति या दुरभिसन्धि की गन्ध सूँघेंगे। इसलिए राजतन्त्र के द्वारा इस प्रकार के प्रयत्न या प्रयोग जब कभी हुए हैं, उन्हें असफलता ही हाथ लगी है। यह क्षेत्र वस्तुतः धर्म और दर्शन का है। बौद्धिक, नैतिक एवं सामाजिक क्रान्ति के लिए विचारणा का स्तर बहुत गहराई से बदलना होगा। उथला बदलाव कोई स्थिर परिणाम उत्पन्न नहीं करेगा। इस प्रयोजन की पूर्ति में केवल धर्मतन्त्र ही समर्थ हो सकता है।

राजनैतिक स्तर पर बाल-विवाह, छुआ-छूत निवारण, दहेज उन्मूलन, व्यभिचार विरोधी कानून बने हुए हैं, पर उनको कितना मान मिला और कितना परिणाम निकला यह सबके सामने है।

भौतिक सुधार कराना राजतन्त्र का क्षेत्र है। भावनात्मक सुधार के लिए प्रजातन्त्र के वातावरण में केवल धर्मतन्त्र ही समर्थ हो सकता है। प्रजातन्त्र हटाकर अधिनायकवाद आना है तो आतंक के आधार पर विचार परिवर्तन भी सम्भव है, पर वह प्रयोग महँगा है। व्यक्ति की विचार स्वतन्त्रता अपहृत हो जाने पर वह एक मशीन मात्र रह जाता है और सौंस्कृतिक प्रगति की जिस महान प्रक्रिया ने मानव जाति को यहाँ तक पहुँचाया उसका द्वार बन्द हो जाता है। हम प्रजातन्त्र पसंद करते हैं। उसमें बहुत खूबियाँ और सम्भावनाएँ सन्निहित हैं। फिर प्रजातन्त्र की परिधि में जनमानस का निर्माण करना धर्म एवं अध्यात्म का ही क्षेत्र रहता है।

हम राजनीति से अलग नहीं हैं, न उसका मूल्य कम कर रहे हैं। बात इतनी भर है कि हम जड़ में खाद, पानी लगाने वाले माली बने रहना चाहते हैं। फूल और फल का व्यापार दूसरे लोग करें, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है और न ही ईर्ष्या। हम अनुभव करते हैं कि उथले राजनीतिज्ञों की अपेक्षा हम अधिक ठोस और अधिक महत्वपूर्ण नीति अपना रहे हैं और हमारे प्रयत्नों का फल किसी भी राजनैतिक पार्टियों की अपेक्षा अधिक सत्परिणाम उत्पन्न करेगा। गाँधी जी का जनमानस निर्माण का काम अधूरा रह गया, हमें उनके शेष काम को पूरा करने वाले कुली, मजदूर की तरह जुटे रहना मंजूर है। दूसरे लोग अपने तप का प्रतिफल चरखें-चखतें रहें। अपने मुँह से उसके लिए लार टपकने वाली नहीं है। हम स्वस्थ राजनीति के विकसित हो सकने की सम्भावना वाला भवन बनाने में नींव के पत्थर मात्र बनकर रहेंगे और जो भी हमारे प्रभाव सम्पर्क में आएगा, उसे इसी दिशा में प्रेरित, आकर्षित करते रहेंगे।

इस सन्दर्भ में युग ऋषि ने समाज के प्रबुद्ध जनों को लक्ष्य करके उनसे भी इसी दिशा में प्रयास करने की अपील की है। उनके कथन का सारांश कुछ इस प्रकार है— “धर्म क्षेत्र में कार्य कर रहे अन्य संगठन भी इस दिशा में सार्थक प्रयास कर सकते हैं। इसके लिये उन्हें धर्मतन्त्र के मर्म को समझते हुए सम्प्रदाय तन्त्र से उपर उठकर सोचना होगा। धर्म उस अनुशासन का नाम है, जो मनुष्य को पशुता की ओर जाने से रोककर देवत्व की दिशा में प्रेरित करता है। जैसे शारीरिक व्यायाम वही श्रेष्ठ है जो शारीरिक आरोग्य और स्वास्थ्य प्रदान करें, उसी प्रकार वही धार्मिक आचार व्यवहार श्रेष्ठ है, जो मनुष्यों का चारित्रिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य उत्तम बना सकें।”

इस दिशा में कार्य करने वाले सामाजिक संगठनों को ‘प्रजातन्त्र’ के पक्ष में ‘पार्टी तन्त्र’ से उपर उठना होगा।

उत्तर— आप के विचार बहुत महत्वपूर्ण है। अगले अंक में हम इसकी समीक्षा प्रसारित करेंगे।

सूचना

अब तक ए टू जेड टीवी चैनल से प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:30 बजे, शनिवार रात 8 बजे, रविवार और सोमवार को भी रात 8 बजे, विचार—मंथन प्रसारित होता रहा है। अब उसका समय बदल गया है। अब प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 6 बजे, शनिवार और रविवार को रात 8 बजे तथा प्रतिदिन रात 11:30 बजे प्रसारित होता है। नये समय के अनुसार आप ये टीवी कार्यक्रम देखने-सुनने की कृपा करें। यह कार्यक्रम पहले की तरह ही रिलायंस छतरी के 425 नम्बर चैनल, ए टू जेड में प्रसारित होता है।